भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 12
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार के अतिरिक्त अवसर

12. श्री मनोज तिवारी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दस वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई विकास योजनाओं के परिणामस्वरुप देश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी अभिलेखों के अनुसार विगत पांच वर्षों के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए राष्ट्रीय शहरी युवा रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों का सरकारी डेटा स्रोत है जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	यूआर (% में)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2
2023-24	58.2	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17 करोड़ है।

देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल (www.ncs.gov.in) लॉन्च किया है जिसमें पोर्टल के माध्यम से रोजगार खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, इंटर्नशिप आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान (15.11.2024 तक), एनसीएस पोर्टल पर 1.12 करोड़ रिक्तियां पोस्ट की गईं और 2015 में पोर्टल की शुरुआत के बाद से, इस पोर्टल पर 3.53 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गईं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 'माय भारत' मंच भी प्रारंभ किया है जो युवाओं को सार्थक गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से पोर्टल में उपस्थित विभिन्न संगठनों के माध्यम से युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करता है। माय भारत पोर्टल की कल्पना युवाओं के विकास और युवाओं द्वारा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रौद्योगिकी-संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है, जिसका प्रमुख लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए पांच योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****